तिब्बत देश

अरुणाचल पर चीन की नीति भारत के लिए एक दैवी मौका

इधर पिछले कई दिनों से भारत–चीन संबंधों में खटास का नया दौर शुरू हो गया है। चीन सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कई गोले नई दिल्ली पर दागे हैं जिन्होंने भारत सरकार को विचलित कर दिया है। चीन सरकार को विदेश नीतियां बनाने की सलाह और दिशा निर्देश देने वाले एक सरकारी थिंक टैंक (शोध संस्थान) ने दो महीने पहले अपने एक विशेषज्ञ के छद्म नाम से एक विश्लेषण प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि भारत एक झूठमूठ का देश है जो जातियों और धर्मों के घालमेल से बना हुआ है और टूटने के कगार पर है। लिहाजा चीन सरकार को नियोजित तरीके से प्रयास करके और वहां के तमिलों, असमियों, कश्मीरियों आदि आदि को सीधा सहयोग देकर भारत के कम से कम बीस टुकड़े कर देने चाहिएं। भारतीय विरोध के जवाब में चीन ने इसे 'एक विद्वान की व्यक्तिगत राय' कहकर शांत करने की कोशिश की लेकिन इसके साथ–साथ इस लेख को कई सरकारी प्रकाशनों में छाप भी डाला।

अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताते हुए चीन सरकार पहले भी कई बार चीन यात्रा पर जाने वाले अरुणाचली सांसदों और अधिकारियों को इस आधार पर चीनी वीज़ा देने से मना करती आयी है कि वे 'चीनी नागरिक' होने के नाते बिना वीज़ा वहां आ सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों उसने तब हद कर दी जब एशिया विकास बैंक से उधार लेने की भारत की एक अर्जी को चीन सरकार ने यह कहकर रद्द करवा दिया कि अरुणाचल प्रदेश एक विवादास्पद इलाका है और इस आवेदन में अरुणाचल प्रदेश की विकास परियोजनाओं की राशि भी शामिल है।

पिछले एक दो साल से चीन में ऐसे लेख कई बार छप चुके हैं जिनमें चीन सरकार से सवाल किया जाता है कि वह 'दक्षिणी तिब्बत' को भारत से कब 'मुक्त' कराएगी। चीन की दलील है कि क्योंकि तिब्बत चीन का हिस्सा है इसलिए उसकी संस्कृति से मेल खाता अरुणाचल भी उसका है। उसका कहना है कि तिब्बत से जुड़े अरुणाचल के तावांग इलाके में छठे दलाई लामा सेयांग ग्यात्सो पैदा हुए थे। चीन यह भी कहता है कि 1914 के शिमला समझौते के तहत यह इलाका भारत में शामिल किए जाने से पहले तक वहां से तिब्बत को टैक्स जाता था। कुल मिलाकर चीन इस इलाके में भारत के 90 हजार वर्ग किमी इलाके पर दावा जता रहा है।

कुछ समय पहले भारतीय राष्ट्रपति की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने भारी आपत्ति खड़ी की थी। अब वहां डा. मनमोहन सिंह की चुनाव यात्रा पर चीन के सरकारी प्रवक्ता ने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसने केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक बिरादरी को भी हैरान किया। अरुणाचल को 'तथाकथित अरुणाचल प्रदेश' कहते हुए उसने डा. मनमोहन सिंह का नाम लेकर उनकी अरुणाचल चुनाव यात्रा को 'उकसाने वाली कार्रवाई' बताया और भारत को चेतावनी दे डाली कि इस 'विवादास्पद' कदम के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यह सलाह भी दे डाली कि उन्हें चीन की चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए।

इससे पहले चीन सरकार अपने नक्शों में अरुणाचल को चीनी हिस्सा दिखाती रही है और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिए गए आश्वासनों के बावजूद सिक्किम को एक अलग देश के रूप में दिखाती आ रही है। लेकिन पिछले दिनों बीजिंग में उसने एक ऐसा नक्शा विदेशी पत्रकारों में बांटा जिसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग देश दिखाया गया है। केवल इतना ही नहीं, उसने अब एक नई कूटनीतिक परंपरा शुरू कर दी है जिसके तहत जम्मू कश्मीर से चीन की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों को उनके भारतीय पासपोर्ट के बजाए एक अलग कागज़ पर वीज़ा जारी किया जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि चीन सरकार जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती।

और अब तिब्बत के निर्वासित शासक दलाई लामा की प्रस्तावित अरुणाचल यात्रा को लेकर तो चीन का भारत विरोधी बुखार सिरसाम के स्तर तक जा पहुंचा है जिसमें रोगी मानसिक संतुलन खोकर अनाप–शनाप बोलने की हालत मे चला जाता है। दलाई लामा इससे पहले भी कई बार अरुणाचल जा चुके हैं। बल्कि तिब्बत पर चीनी कब्जे के अंतिम चरण में 1959 में चीनी सैनिकों से अपनी जान बचाने और भारत में शरण लेने के लिए भागते समय उन्होंने इसी इलाके से भारत में प्रवेश किया था। पहले की तरह इस बार भी उनकी यात्रा का उद्देश्य वहां के प्रतिष्ठित तावांग मठ में धार्मिक प्रवचन देना है।

भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को अरुणाचल यात्रा की अनुमति देने पर आग बबूला चीन सरकार ने न केवल दलाई लामा को चीन के खिलाफ एक 'विध्वंसकारी' बताया बल्कि उसने भारत को चीन के 'भीतरी मामलों' में दखल देने से बाज आने' की घुड़की भी दे डाली। लेकिन इस बार भारत सरकार ने अभूतपूर्व साहस और राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हुए और बिना चीन की तरह आपा खोए चीन सरकार के इस विरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। दलाई लामा भारत के सम्मानित मेहमान हैं। इसलिए उन्हें भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी है।" पिछले 60 साल के भारत–चीन संबंधों में शायद यह पहला अवसर है जब भारत सरकार ने बिना अपना परंपरागत दब्बूपन दिखाए चीनी घुड़कियों का ऐसा आत्म सम्मान भरा जवाब दिया है। इस मामले में चीन दलाई लामा से भी खासा नाराज है और उन्हें 'गद्दार' मानता है। अरुणाचल विवाद पर दो साल पहले दलाई लामा सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि मेरे पूर्ववर्ती 13वें दलाई लामा ने भारत के साथ शिमला संधि करके इस इलाके को भारत का हिस्सा माना था। इसलिए मेरी यह नैतिक और कूटनीतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने से पहले राष्ट्राध्यक्ष और अपने पूर्ववर्ती के निर्णय का सम्मान करूं।

अरुणाचल और दलाई लामा के ताजा मुद्दे का एक सुखद पहलू यह है कि भारत की कूटनीति में, खासतौर से चीन के साथ संबंधों के मामले में भारत में एक नई सोच उभर रही है। अब वक्त आ गया है कि चीन के साथ इस विवाद में भारतीय पक्ष को कुछ सीधे–सीधे और दो टूक सवाल उठाने चाहिएं। यह कि 1949 में चीनी गणराज्य के अस्तित्व में आने से पहले तिब्बत एक स्वतंत्रत देश था –– कम से कम 1913 के बाद से तो था ही; कि पिछले 2000 साल से ज्यादा लंबे इतिहास के दौरान अरुणाचल समेत 3500 किमी लंबी भारत–तिब्बत सीमा पर किसी एक दिन के लिए, एक इंच जगह पर भी न तो कोई चीनी सैनिक तैनात था और न टैक्स उगाहने वाला कोई चीनी कारिंदा; कि इस सीमा पर चीन की करेंसी या चीनी डाक का चलन था और न किसी तरह का कोई चीनी कानून यहां लागू था; कि 1914 की शिमला संधि में भारत,तिब्बत और चीन तीन अलग–अलग देशों के तौर पर शामिल हुए थे; कि इस संधि में तत्कालीन तिब्बत सरकार ने अरुणाचल (तब 'नेफा') को भारत का हिस्सा स्वीकार किया था और चीन ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी थी; कि यहां की किसी भी जाति की चीनी जाति से किसी तरह की समानता नहीं है (अरुणाचल की कई जातियों में से एक मोन्पा की संस्कृति समान है लेकिन बेचारे तिब्बती मोन्पाओं का चीन से रिश्ता उपनिवेशवादी गुलामी से ज्यादा कुछ नहीं है) और; यह भी कि चीन ने 1962 युद्ध में तावांग पर कब्जा करने के बाद भी इसे 'भारतीय' इलाका मानकर खाली कर दिया था।

असल में अरुणाचल को लेकर चीन के ताजा रवैये को भारत सरकार को एक दैवीय अवसर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी बेजा करतूतों से चीन ने भारत सरकार को समुचित कारण दे दिया है कि वह अपनी तिब्बत नीति पर नए सिरे से विचार करे। दब्बूपने में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लेने के बजाए अब भारत को तिब्बत पर चीन के अनैतिक और गैरकानूनी कब्जे को चुनौती देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक उपनिवेशवादी मुद्दे के रूप में पेश करना चाहिए। भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक रवैये की यही सटीक काट हो सकती है।

– विजय क्रान्ति

तिब्बत के बाद सिंकियांग में मुसीबत

दोनो क्षेत्रों में चीनी उपनिवेशवाद का बोलबाला

– ब्रह्म चेलानी

चीन सरकार ने तेल खनिज सम्पन्न सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) में सेना भेजकर राजधानी उरुम्ची में और काशगार जैसे शहरों तक फैली उइगुर विद्रोह की आग को ठंडा करने करने में भले ही थोड़ी बहुत सफलता पा ली हो लेकिन इन अल्पसंख्यकों का विद्रोह और 2008 में समूचे तिब्बत में हुआ विरोध प्रदर्शन चीन की जोर–जबर्दस्ती की आदत को दर्शाता है।

चीनी गणराज्य के करीब 60 प्रतिशत हिस्से वैसे हैं जो इतिहास में हान चीनियों के सीधे अधीन नहीं थे। वस्तुतः चीन की दीवार हन शासक के बाहरी सुरक्षा परिक्षेत्र के रूप में बनाए गए थे। आज सिंकियांग और तिब्बत ही चीन के कुल भूभाग का करीब आधा है।

तिब्बत और सिंकियांग में हुई हिंसा के बीच महत्वपूर्ण समानताएं हैं। दोनों इलाकों में जातीय हिंसा तभी भड़की जब अधिकारियों ने ल्हासा और उरुम्ची में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया।

एक ओर तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में 60 वर्ष आने की सालगिरह के तौर पर सर्वाधिक बड़ी पार्टी के आयोजन की तैयारी कर रही है और दूसरी ओर वह किसी भी विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए आसान्य तौर–तरीके अपना रही है। चार जून 1989 को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के तियेनआनमेन स्क्वेयर जनसंहार की 20वीं सालगिरह पर इस बार किसी तरह की कोई वारदात नहीं हो पायी और इसका मुख्य कारण था– बीजिंग में भारी सुरक्षा के बंदोबस्त। तिब्बत में सुरक्षाकर्मियों द्वारा की गई किलेबंदी की वजह से तिब्बती आंदोलन और दलाई लामा के भागकर भारत जाने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी गत मार्च में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। आत्म विश्वास से ओत–प्रोत लग रहे चीन ने 28 मार्च को तिब्बत पर अपने कब्जे को 'दास मुक्ति दिवस' की स्वर्ण जयंती के रूप में मनाकर उपनिवेशवा को मुक्ति दिखाने की कोशिश की।

पूर्वी तुर्किस्तान को चीन में शामिल करने के 60 वर्ष पूरे होने के बावजूद उइगुरों का आंदोलन चीनी तानाशाही के लिए करारा झटका है। तिब्बत और सिंकियांग में आर्थिक विकास के नाम पर केवल खनिजों की लूट हुई है और इससे वहां के लोग हाशिए पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों को तो मामूली कमाई वाली नौकरियां मिल रही हैं, जबकि हान लोगों (चीनियों) को मोटी–मोटी रकम वाली नौकरियां।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन में प्रमुख गैर–हान संस्कृतियों पर खतरा मंडराने लगा है। स्कूली स्तर पर थोपी गई अपने तरह की शिक्षा से लेकर मठों में राजनीतिक पुनर्शिक्षा तक, इन सारी चीनी नीतियों की वजह से तिब्बत और सिंकियांग के लोगों में असंतोष की भावना पैदा हुई है। तिब्बती और उइगुर भाषाएं स्थानीय स्कूलों से गायब होती जा रही हैं। उनके पर्यावरण को तेजी से पहुंचाए जा रहे नुकसान ने तिब्बतियों और उइगुरों के मन में अपनी पहचान और आजादी के प्रति संवेदना तेज कर दी है।

हम सिंकियांग में हताहतों और गिरफ्तारियों की संख्या के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि तिब्बत या सिंकियांग में परिस्थितियां उलट होने के प्रथम संकेत के साथ ही चीन सरकार स्थानीय इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं बाधित कर देती है और कर्फ्यू एवं मार्शल लॉ के जरिये सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर देती है। सिंकियांग हिंसा में मारे गए लोगों की आधिकारिक संख्या पर शायद कम ही लोग विश्वास करेंगे। चीन ने तिब्बत में 2008 में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या केवल 13 बताई थी, जबकि निर्वासन तिब्बत सरकार ने यह आंकड़ा 220 का बताया था।

तिब्बत और सिंकियांग में हुई हिंसा के बीच महत्वपूर्ण समानताएं हैं। दोनों इलाकों में जातीय हिंसा तभी भड़की जब अधिकारियों ने ल्हासा और उरुम्ची में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। तिब्बत घटना के तुरंत बाद चीन ने तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा पर इसके लिए आरोप मढ़ दिए। चीन सरकार ने उरुम्ची में हुए आंदोलन के लिए निर्वासित उइगुर नेताओं, खासकर वाशिंगटन स्थित रुबिया कादिर को दोषी ठहराया। हालांकि सुश्री कादिर ने अपने छह महत्वपूर्ण साल चीन की जेल में बिताए हैं और उनके दो पुत्र आज भी सिंकियांग की जेल में बंद हैं, इसके बावजूद वह हिंसा की पक्षधर कभी नहीं रहीं।

तिब्बत और सिंकियांग को जबर्दस्ती चीन में मिलाने की नीतियां माओ जेदोंग के भू–गलियारे के निर्माण के बाद शुरू हुई। माओ जेदोंग ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को हड़पने के बाद दोनों इलाकों में अपने गलियारे बनाए थे। यह इलाका स्विटजरलैंड के बराबर है। चीन की जातीय समस्या का समाधान तबतक नहीं हो सकता जबतक वहां सांस्कृतिक समांगता नहीं रुकती। तिब्बत में 2008 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद 2009 उइगुर आंदोलन के रूप में याद किया जाएगा।

जुलाई में उरुमची के दंगों में चीनी पुलिस – उपनिवेशवादी दमन

सिंकियांग दंगों तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पहुंच हमारी सफलताः चीन

चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी का नया पैतरा

सिंकियांग दंगों पर चीनी कम्युनिस्ट की प्रोपेगैंडा मशीनरी का रवैया अनोखा रहा है। उइगुरों के दावे के मुताबिक, चीन के पश्चिमी उपनिवेा सिंकियांग में फैले दंगों में 800 से अधिक नागरिक मारे गए थे। इस साल 5–6 जुलाई के बीच जब सिंकियांग की राजधानी उरुम्ची और अन्य शहरों में उइगरों ने चीनी कब्जे के खिलाफ विद्रोह किया तो वहां बीजिंग से आए बड़ी संख्या में विदेशी पत्रकार मौजूद थे। असल में चीन सरकार इन्हें वहां यह दिखाने के लिए लायी थी कि चीनी कब्जे के बाद इस इलाके की कितनी तरक्की हुई है। इसका नतीजा यह निकला कि विदेशी पत्रकारों की उपस्थिति के कारण चीन सरकार इन दंगों को दुनियाभर में सुर्खियां बनने से नहीं रोक सके। लेकिन अब चीनी अधिकारी सिंकियांग पर घटनाओं को मिले अंतर्राष्ट्रीय प्रचार को अपनी सूचना नीति के 'खुलेपन' का नतीजा बनाकर इसके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।

चीन की सरकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, चीन के केंद्रीय और क्षेत्रीय प्रोपेगैंडा कार्यालयों का निष्कर्ष है कि उरुम्ची में दंगे भड़कने के बाद मीडिया को वहां जाने देने की रणनीति सफल रही है। प्रोपेगैंडा कार्यालयों का कहना है कि 5 जुलाई को भड़के दंगों के तुरंत बाद एक केंद्रीय और स्थानीय टास्क फोर्स बुला ली गई थी क्योंकि उस समय वहां बड़ी संख्या में विदेशी पत्रकार कवरेज के लिए मौजूद थे। दंगे भड़कने की वजह यह थी कि दक्षिण चीन की एक फैक्टरी में कुछ उइगुर श्रमिकों पर हान चीनी मजदूरों के हमले में कई उइगुर मजदूर मारे गए थे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले साल 14 मार्च को ल्हासा में भी बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे। लेकिन दंगों के बाद जब पूरे तिब्बत में प्रदर्शन होने लगे तब तिब्बत में विदेशी मीडिया के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वहां मौजूद विदेशियों को बाहर निकाल दिया गया थ। उस समय खबरों को पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया था। विश्व मीडिया के पास चीनी सरकार द्वारा प्रायोजित खबरों, तस्वीरों और टीवी फुटेज के सिवाय कुछ नहीं पहुंच पा रहा था।

लेकिर सिन्हुआ के मुताबिक, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगैंडा विभाग के उपप्रमुख और राज्य परिषद सूचना कार्यालय के निदेशक वांग जेन ने कहा, ''मीडिया से संबंधित खुलापन विश्वास से उपजा है। सचाई सामने आने के कारण अफवाहों पर रोक लग गई।''

चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी सिंकियांग के मीडिया कवरेज पर इसी तरह का संतोष व्यक्त किया है। लेकिन उन रिपोर्टरों और मीडिया घरानों को फटकार लगाई गई है जिन्होंने 'पक्षपातपूर्ण कवरेज' किया। चीनी मीडिया और इंटरनेट के टिप्पणीकारों ने भी आरोप लगाया है कि पश्चिमी मीडिया तिब्बत या उइगुर मुद्दों के कवरेज के दौरान चीन के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लेता है।

सरकार के 'खुलेपन' के दावों के बाद भी सच्चाई यह है कि कि उरुम्ची में पहले से मौजूद विदेशी संवाददाता दंगे भड़कने पर जब किसी तरह काशगर शहर पहुंचे तो वहां उन्हें होटल से बाहर निकलने से रोक दिया गया। यही नहीं, दंगे शांत होने के बाद उन्हें जबर्दस्ती हवाई अड्डे ले जाकर विमान में बैठा दिया गया। दंगों के बाद जुलाई में सिंकियांग लौटने वाले पत्रकारों ने पाया कि स्थानीय लोगों को उनकी मौजूदगी के बारे में अधिकारियों के सामने तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

काशगर जाने के इच्छुक कुछ विदेशी पर्यटकों ने भी अपनी उड़ानें रद्द कर करवा दी हैं। इसी तरह, 2008 में तिब्बत विदेशी पर्यटकों के लिए ज्यादातर समय बंद रहा जिससे वहां के पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ। इस साल मार्च में भी विदेशी पर्यटकों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, ल्हासा में काम करने वाले ज्यादातर गैरसरकारी संगठनों को भी प्रदर्शन के बाद तिब्बत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया।

सरकार के 'खुलेपन' के दावों के बाद भी सच्चाई यह है कि कि उरुम्ची में पहले से मौजूद विदेशी संवाददाता दंगे भड़कने पर जब किसी तरह काशगर शहर पहुंचे तो वहां उन्हें होटल से बाहर निकलने से रोक दिया गया। बाद में उन्हें जबर्दस्ती हवाई अड्डे ले जाकर विमान में बैठा दिया गया।

तिब्बती आजादी के बिना चीन में भी आजादी नहीं आएगी

चीन और तिब्बत के विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों और वकीलों का जेनेवा में अनूठा सम्मेलन

कॉन्फ्रेंस की आम राय यह है कि तिब्बती जनता को स्वाधीनता मिलनी चाहिए और तिब्बती संस्कृति को खत्म होने से बचाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस का मानना है कि स्वाधीनता सर्वोपरि है और मानव जाति की तमाम संस्कृतियों में तिब्बती संस्कृति अनमोल खजाना है। तिब्बत की आजादी के बिना चीन में भी आजादी नहीं आएगी। तिब्बती संस्कृति का विनाश तिब्बती जनता के लिए त्रासदी तो होगी ही, चीनी जनता के लिए भी शर्म की बात होगी।

स्विटजरलैंड, 8 अगस्त तिब्बत के मुद्दे पर एक अनोखा सम्मेलन जेनेवा में छह अगस्त को हुआ जिसमें तिब्बत और चीन के विद्वान, लेखक, पत्रकार, वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन के बाद पारित प्रस्ताव में तिब्बत की आजादी का इंटरनेशनल फेलोशिप ऑफ रीकॉन्सिलिएशन (आईएफआर) एवं स्विस तिबेतन फ्रेंडशिप एसोसिएशन (एसटीएफए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में पूरी दुनिया से तिब्बत और चीन के सौ से अधिक प्रतिनिधि आए।

आईएफआर के श्री जोनाथन सिसन ने कहा, ''इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच बेहतर समझ बनाना और तिब्बत मुद्दे के शांतिपूर्ण हल के लिए रास्ता अख्तियार करना है। एसटीएफए के डॉ. ताशी थाकत्सांग ने कहा, ''यह चीन और तिब्बत दोनों की जनता के हित में है। साथ ही इससे चीन के दीर्घकालिक विकास का उद्देश्य पूरा होगा तथा एशिया में शांति और स्थायित्व में सहयोग मिलेगा।

इस सम्मेलन में मुख्य संबोधन परमपावन दलाई लामा का रहा, जबकि अस्सी के दशक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव झाओ जियांग के नेतृत्व वाले राजनीतिक सुधार आयोग में सेवा उपलब्ध करा चुके चीनी विद्वान श्री यान जियाकी अतिथि थे। श्री यान जियाकी चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज (सीएएसएस) के राजनीतिक अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे हैं तथा 'ए टेन ईयर हिस्ट्री ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशन' सहित अनेक पुस्तकें लिखी हैं। 1951 में तिब्बत पर चीन के कब्जे से पहले सदियों से चीनी और तिब्बती जनता एक–दूसरे से जुड़ी रही है और धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक–दूसरे को लाभ पहुंचाती रही है। पिछले पचास–साठ साल से राजनीतिक विवादों के कारण इन रिश्तों में कड़वाहट आई है।

गत वर्ष समूचे तिब्बत में हुए विरोध–प्रदर्शन यह दर्शाते हैं कि तिब्बत में चीनी सरकार की नीतियों को लेकर तिब्बतियों में व्यापक असंतोष है। अनेक अवसरों पर दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बती नागरिक इतिहास पर आधारित कोई भी मांग नहीं कर रहे हैं। अपने 10 मार्च 2009 के बयान में भी उन्होंने कहा था, ''हमें भविष्य की ओर ध्यान देने और पारस्परिक लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। हम तिब्बतियों के लिए सार्थक और वैध स्वायत्तता की तलाश में हैं, जिससे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दायरे के दायरे में तिब्बतियों के रहने का अवसर मिल सकेगा।''

चीन–तिब्बत कॉन्फ्रेंस का दस्तावेज

जिनेवा में 6–8 अगस्त 2009 तक आयोजित इस चीन–तिब्बत 'फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड' कॉन्फ्रेंस में चीनी और तिब्बती विद्वानों, शिक्षाशास्त्रियों, लेखकों और मानवाधिकारों के पैरोकारों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य चीनी जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह बताना है कि तिब्बती संस्कृति एवं जीवनशैली गंभीर खतरे में है और चीनी प्रशासन तिब्बती लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य तिब्बती जनता के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देने और उनकी अनूठी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कारगर उपायों की रूपरेखा भी खींचना है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन परम पावन दलाईलामा ने किया।

इन लक्ष्यों के आधार पर कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित साझा आधार पर पहुंचीः

(क) बुनियादी मूल्य और सिद्धांत

वैश्विक मानवाधिकार घोषणापत्र द्वारा स्थापित वैश्विक मूल्य, जिनमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासन, मानवाधिकार, समानता और विभिन्न संस्कृतियों का सहअस्तित्व शामिल है, बुनियादी आध्यात्मिक मूल्य और सिद्धांत हैं। कॉन्फ्रेंस ने इन मूल्यों और सिद्धांतों का अनुमोदन किया है।

(ख) तिब्बती मसले का कारण और प्रकृति

1. तिब्बती मसले का मूल कारण चीनी जनता और तिब्बती जनता के बीच टकराव नहीं है, बल्कि तिब्बत में चीनी गणराज्य का स्वेच्छाचारी शासन और तिब्बती संस्कृति का विनाश है।

2. बीजिंग सरकार का यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है कि 'तिब्बत हमेशा चीन का अंग रहा है'।

3. तिब्बती संस्कृति, धर्म, भाषा और जीवनशैली खत्म होने के कगार पर हैं।

4. तिब्बती जनता को राष्ट्रीय स्वाधीनता, राजनैतिक भागीदारी और धार्मिक आस्था के अधिकार सहित उनके मौलिक मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है।

5. चीनी सरकार का सरकारी मीडिया तिब्बत मसले को तोड़मरोड़कर पेश करता है और चीनी जनता तथा तिब्बती जनता के बीच टकराव पैदा

करता है।

(ग) तिब्बत मसले को हल करने के तरीके

1. तिब्बती जनता के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। इनमें राजनैतिक भागीदारी और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं।

2. तिब्बती मसले का हल चीन के लोकतंत्रीकरण से जुड़ा है।

3. चीनी जनता को हान उग्रराष्ट्रीयता पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और तिब्बती संस्कृति तथा जीवनशैली का सम्मान करना चाहिए।

4. चीनी सरकार को कानून के शासन के सिद्धांत पर चलना चाहिए।

5. परम पावन दलाईलामा के स्वदेश लौटने के मौलिक अधिकार का सम्मान होना चाहिए।

(द) तिब्बत की निर्वासन सरकार के लिए सुझाव

1. चीनी और तिब्बती जनता के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान और भावात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दुनियाभर में चीन–तिब्बत मैत्री संघों, चीन–तिब्बत मंचों और सिविल सोसाइटी संगठनों की स्थापना करना।

2. चीनी और तिब्बती विद्वानों के लिए एक शोध संस्थान की स्थापना करना। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को जुटाने के लिए तिब्बती संस्कृति और इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा देना होगा।

3. चीन परम पावन दलाईलामा से संबंधित सूचना को अवरुद्ध करता रहा है और तिब्बत मसले पर निरंकुश रवैया अपनाता रहा है। चीन के इस कदम को निश्फल बनाने के लिए जवाबी कदम उठाना ताकि चीनी जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक स्वतंत्र सूचना पहुंच सके।

4. परम पावन दलाईलामा के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना ताकि वे चीनी समुदाय के बीच अपने आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार–प्रसार कर सकें।

चीन–तिब्बत कॉन्फ्रेंस की आम राय यह है कि तिब्बती जनता को स्वाधीनता मिलनी चाहिए और तिब्बती संस्कृति को खत्म होने से बचाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस का मानना है कि स्वाधीनता सर्वोपरि है और मानव जाति की तमाम संस्कृतियों में तिब्बती संस्कृति अनमोल खजाना है। तिब्बत की आजादी के बिना चीन में भी आजादी नहीं आएगी। तिब्बती संस्कृति का विनाश तिब्बती जनता के लिए त्रासदी तो होगी ही, चीनी जनता के लिए भी शर्म की बात होगी। तिब्बती संस्कृति का विनाश पूरी मानव जाति के लिए अपूरणीय क्षति होगी।

चीन अरुणाणल प्रदेश पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं

हांगकांग के अखबार पर चीन नाराज़

बीजिंग, 8 अगस्त   हांगकांग से प्रकाशित होने वाले एक चीनी अखबार मिंग पाओ ने यह कहकर चीनी अधिकारियों में खलबली मचा दी कि बीजिंग अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते नई दिल्ली पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन पर चीन के नियंत्रण को मान्यता दे दे।

अखबार ने कहा कि चीन 120,000 वर्ग किमी विवादास्पद क्षेत्र का केवल 28 प्रतिशत चाहता है। चीन यह भी चाहता है कि नई दिल्ली विवादास्पद क्षेत्र के मध्य में स्थित 2,000 वर्ग किमी इलाके पर अपना दावा छोड़ दे। चीन का दावा है कि यह इलाका तिब्बत का हिस्सा है इसलिए चीन का है। वह अक्साई चिन के 33,000 वर्ग किमी क्षेत्र को भी अपने कब्जे में रखना चाहता है। यदि भारत 2,000 वर्ग किमी इलाका छोड़ दे तो सीमा विवाद जल्दी हल हो सकता है।

लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने मिंग पाओ की रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग यु ने अखबार की रिपोर्ट को आधारहीन बताते हुए कहा कि चीन मसले का निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर मान्य हल निकालने के लिए भारत के साथ संयुक्त प्रयास करने का इच्छुक है।

सरकारी मीडिया ने सरकार संचालित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॅन्टेम्पोरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक स्कालर फू सिआओचियांग के हवाले से कहा कि मिंग पाओ की रिपोर्ट दरअसल सीमा विवाद पर भारतीय नजरिए को दर्शाती है।

प्रभावशाली मिंग पाओ, जिसके दो संस्करण कनाडा से भी निकलते हैं, की टिप्पणी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन और चीनी स्टेट काउंसिलर दाई बिंगुओ के बीच 13वें चक्र की सीमा वार्ता शुरू होने से ठीक पहले आई।

रिपोर्ट से आभास मिलता है कि चीन अक्साई चिन पर कब्जे के लिए कितना परेशान है। अक्साई चिन पाकिस्तान से लगे अशांत सिंकियांग प्रांत से सटा हुआ है। उल्लेखनीय है कि सिंकियांग, जहां हाल में खूनी दंगे हुए थे, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान राष्ट्र के निर्माण के लिए चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा है। मिंग पाओ ने चीनी अधिकारियों को सलाह दी कि वे जल्दीबाजी में ऐसा कोई फैसला न लें जिसो भावी पीढ़ियां उनकी आलोचना करें।

सरकारी मीडिया ने सरकार संचालित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॅन्टेम्पोरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक स्कालर फू सिआओचियांग के हवाले से कहा कि मिंग पाओ की रिपोर्ट दरअसल सीमा विवाद पर भारतीय नजरिए को दर्शाती है।

चीन ने तिब्बत पर स्पेन को धमकी दी

स्पेन की अदालत में चीनी नेताओं पर नरसंहार जैसे अपराधों के मुकदमे से चीन बौखलाया

लिआंग गुआंगली, 'फायुल' से साभार

धर्मशाला, 21 अगस्त चीन ने एक स्पेनिश कोर्ट में चीनी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के न्यायिक अनुरोध को ठुकरा दिया और स्पेन सरकार से जांच–पड़ताल बंद करने को कहा। चीनी अधिकारियों पर 'तिब्बती जनता के खिलाफ नरसंहार और अन्य कई अपराध' करने का आरोप है।

स्पेन स्थित चीनी दूतावास ने अपनी पहली लिखित प्रतिक्रिया में कहा कि स्पेन ने ''अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित राज्य के अधिकार क्षेत्र और प्रतिरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों' का उल्लंघन किया है। स्पेन का अनुरोध चीन और स्पेन के बीच आपराधिक मामलों पर हुई न्यायिक सहायता संधि के अंतर्गत नहीं आता।''

स्पेनी कानून के तहत दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवाधिकारों, खासकर नरसंहार जैसे अपराधों के लिए किसी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। स्पेनिश न्यायपालिका ने इस सिद्धांत को 2005 में अपनाया था जिसके तहत स्पेनिश कोर्ट जातिसंहार के मामलों और मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं,चाहे वे अपराध कहीं भी हुए हों और प्रतिवादी की नागरिकता कुछ भी हो।

स्पेनी कानून के तहत दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवाधिकारों, खासकर नरसंहार जैसे अपराधों के लिए किसी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। स्पेन के एक तिब्बत समर्थक संगठन ने तिब्बत में नरसंहार और अन्य अत्याचारों के लिए जिम्मेदार कई चीनी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया हुआ है। स्पेन की राष्ट्रीय कोर्ट ने, जो मानवता और जातिसंहार के खिलाफ मामले देखता है, तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स द्वारा पिछले साल 9 जुलाई को दायर मुकदमे को ''युनिवर्सल कॉम्पिटेंस'' के सिद्धांत के तहत सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। स्पेनिश न्यायपालिका ने इस सिद्धांत को 2005 में अपनाया था जिसके तहत स्पेनिश कोर्ट जातिसंहार के मामलों और मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं,चाहे वे अपराध कहीं भी हुए हों और प्रतिवादी की नागरिकता कुछ भी हो।

लेकिन चीन ने कहा है कि वह इस मामले में किसी तरह का न्यायिक सहयोग नहीं करेगा। उसने स्पेन को सलाह दी कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून संबंधी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे, आपराधिक मामलों में न्यायिक सहायता संबंधी संधि का उल्लंघन न करे और मामले को बंद करे। मैड्रिड स्थित चीनी दूतावास ने स्पेन के न्याय मंत्रालय द्वारा जारी उस रोगेटरी ऑर्डर को भी लौटा दिया जिसमें चीनी नेताओं को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया था।

स्पेनिश जज सांतिआगो पद्रेज ने 5 मई को चीनी न्याय मंत्रालय को आठ चीनी नेताओं के खिलाफ फैसले से अवगत कराया। इन नेताओं में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पार्टी सचिव झांग चिंगली भी शामिल हैं। चीनी नेताओं पर मार्च 2008 में तिब्बती प्रदर्षनकारियों को कुचलने का आरोप है। पेद्रेज ने मई में चीन से अनुरोध किया था यदि प्रतिवादी स्पेन नहीं आ सकते हैं तो उनसे चीन में भी पूछताछ की जा सकती है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, मैड्रिड स्थित चीनी दूतावास के एक प्रतिनिधि ने स्पेनिश अधिकारियों से बातचीत में संकेत दिया कि यदि पेद्रेज चीन जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि स्पेनी कांग्रेस ने 19 मई को एक प्रस्ताव पारित कर जजों के अधिकार क्षेत्र को उन मामलों तक सीमित कर दिया जिनका स्पेन से संबंध है। इस तरह, तिब्बती मुकदमों के कमजोर पड़ जाने का खतरा पैदा हो गया है।

बहरहाल, चीन के दबाव के बावजूद, पेद्रेज ने हाल में घोषणा की कि तिब्बती मुकदमों में से एक का विस्तार कर उसमें 30 सितंबर 2006 की नांगपाला शूटिंग की जांच भी शामिल की जाएगी। नांगपा ला शूटिंग में चीनी सीमा बलों ने एक 17 वर्षीया भिक्षुणी को उस समय गोली मार दी थी जब वह तिब्बत सीमा पार कर नेपाल में घुसने की कोशिश कर रही थी।

मुकदमे में चीन के रक्षा मंत्री लिआन गुअंगली, राज्य सुरक्षा मंत्री गेंग हुइचांग, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री मेंग जिआंझम, तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव झांग चिंगली, पोलितब्यूरो के सदस्य वांग लेकुआन, जातीय मामलों से संबंधित आयोग के मुखिया ली देझू, ल्हासा में पीपुल्स लिबरेषन आर्मी के कमांडर जनरल तोंग गुइशन और चेंगदू मिलिट्री कमान में राजनैतिक कमिसार झांग गुइहुआ शामिल हैं। इनमें से झांग किंगली, वांग लेकुआन और ली देझू पर तिब्बतियों और अन्य अशांत जातीय अल्पसंख्यकों के दमन की साजिश रचने का आरोप है।

राष्ट्रीय कोर्ट के एक अन्य जज तिब्बत में 1980 और 1990 के दशक में हुए कथित जातिसंहार की जांच कर रहे हैं। तीन पूर्व तिब्बती राजनैतिक बंदियों—पाल्देन ग्यात्सो, जामपेल मोंलम और भागद्रोने इस सिलसिले में उनके सामने गवाही दी।

पिछले साल एक स्पेनिष वकील डॉ. जोज एलिअस एस्टीव और कमिटी डि अपायो एल तिबत (कैट) के एलन कैंटोस तिब्बतियों से यह कहने के लिए भारत आए थे कि स्पेनिष कोर्ट में गवाही दें। इसके पहले भारत ने रोगेटरी कमीषन बैठाने से इनकार कर दिया था। एषियन एज की 17 फरवरी 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कमीषन के बैठ जाने से तिब्बती भारत में गवाही दे सकते थे।

दलाईलामाः चीन में तिब्बतियों के लिए समर्थन बढ़ रहा है

तिब्बत में निष्पक्ष प्रेक्षकों द्वारा जांच की जरूरत है

स्विटजरलैंड, 4 अगस्त दलाईलामा ने कहा है कि पिछले साल तिब्बत में चीन–विरोधी दंगों के दौरान गिरफ्तार किए गए कोई 4,000 लोग अभी भी चीनी जेलों में बंद हैं। उन्होंने वहां हुई हिंसा की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग भी की।

दलाईलामा ने कहा कि तिब्बतियों के हक में चीनी जनता और बुद्धिजीवियों का समर्थन बढ़ता जा रहा है जो उत्साहजनक है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल चीनी सरकार के दमन के कारण पैदा हुई शांति के बावजूद तिब्बत में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

ल्हासा में मार्च 2008 में भड़के चीनी–विरोधी प्रदर्शन पूरे पश्चिमी चीन में फैल गए थे। जवाब में चीन ने तिब्बती इलाकों में फौज झोंक दी, विदेशी मीडिया और पर्यटकों को तिब्बत से बाहर रखा, और सरकार–विरोधी भावनाओं के लिए बौद्ध मठों को दोषी ठहराया। चीन ने दलाईलामा के खिलाफ भी निंदा अभियान तेज कर दिया और उन्हें अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

74 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, परम पावन दलाई लामा ने कहा, ''मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहा हूं कि वे तिब्बत जाएं और पूरी तरह से जांच–पड़ताल करें।''

दलाईलामा ने आगे कहा कि चीन को तिब्बतियों के खिलाफ बल प्रयोग से बचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि तिब्बतियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने से भी रोका जा रहा है।

लेकिन उन्होंने कहा कि तिब्बतियों के खिलाफ भेदभाव और तिब्बत की स्वायत्तता की जरूरत के बारे में चीनी जनता जागरूक हो रही है। यहां तक कि चीनी सरकार के अधिकारी भी बीजिंग के सख्त रवैए से खुश नहीं हैं।

दलाईलामा ने कहा, ''चीनी जनता का एक भाग हमारे साथ एकता दिखा रहा है। चीनी सरकार के कई अधिकारी भी निजी स्तर पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और हमारे साथ एकता दिखा रहे हैं।'' दलाईलामा लूजॉन स्थित हॉकी के एक मैदान में बौद्ध धर्म का उपदेश दे रहे थे जिसमें 6,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उपदेश का यह कार्यक्रम दो दिनों तक चला।

दुनिया के तमाम हिस्सों में दलाईलामा की बहुत प्रतिष्ठा है और वे तिब्बत की स्वायत्तता के लिए चलाए जा रहे अहिंसक अभियान की मुख्य आवाज हैं। तिब्बत लगभग छह दशकों से चीनी शासन के तहत पिस रहा है और दलाई लामा 1959 से निर्वासन में रह रहे हैं।

दलाईलामा ने तिब्बतियों के लिए आजादी की नहीं, स्वायत्तता की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता फिलहाल संभव नहीं दिख रही है। लेकिन उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि वे अंततः अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी लोगों ने तिब्बतियों के समर्थन में पिछले साल 600 से अधिक लेख प्रकाशित किए। इनमें इंटरनेट पर प्रकाशित लेख भी शामिल हैं।

दलाईलामा ने आंग सान सु ची को रिहा करने के लिए बर्मा से अपील की

धर्मशाला 12 अगस्त (फायुल) परम पावन दलाईलामा ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सन सू ची की रिहाई की मांग की है।

तिब्बती नेता ने अपने अधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, ''आंग सान सू ची की नजरबंदी की अवधि बढ़ाए जाने से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। साथी बौद्ध होने के नाते मैं एक बार फिर बर्मी अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे ची को रिहाकर अपनी दरियादिली और समझदारी दिखाएं। ची की रिहाई से न केवल समझौते में मदद मिलेगी, बल्कि सद्भावना का माहौल भी बनेगा।''

घर में नजरबंदी का उल्लंघन करने पर सू ची की सजा की अवधि 11 अगस्त को तीन साल के लिए बढ़ा दी गई। सू ची ने एक अमेरिकी व्यक्ति को अपने लेकसाइड स्थित घर में रहने की इजाजत दी थी। बर्मा के नेता जनरल था श्वे ने सजा की अवधि तीन वर्ष से घटाकर 18 महीने कर दी।

सू ची को मुजरिम ठहराए जाने पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून और अमेरिकी राष्ट्रपति सहित कई विश्व नेताओं ने बर्मा सरकार की कड़ी आलोचना की। लेकिन चीन ने बर्मा सरकार के फैसले का स्वागत किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग यु जियांग ने कहा, ''अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार की न्यायिक प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए।''

एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (एसियान) ने कहा कि सू ची को मुजरिम ठहराए जाने से ''दक्षिणीपूर्वी एशिया की संयुक्त समुदाय की छवि बनाने के उसके प्रयास को झटका लगा है।''

ल्हासा में मार्च 2008 में भड़के चीनी–विरोधी प्रदर्शन पूरे पश्चिमी चीन में फैल गए थे। जवाब में चीन ने तिब्बती इलाकों में फौज झोंक दी, विदेशी मीडिया और पर्यटकों को तिब्बत से बाहर रखा, और सरकार विरोधी भावनाओं के लिए बौद्ध मठों को दोषी ठहराया।

कैमरे की आं

1. प्राग में 10 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय एशिया मानवाधिकार सम्मेलन में सिंकियांग स
2. जी–20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान 24 सितंबर को पिट्सबर्ग में तिब्बत
3. 25 सितंबर को चीनी प्रतिनिधिमंडल की नेपाल यात्रा के दौरान एक तिब्बती क
4. 'धरती बचाओ' पर्यावरण दिवस पर 21 सितंबर को धर्मशाला के नेचुंग मंदिर के
5. 26 सितंबर के दिन कनाडा के वेनकूवर नगर में पहुंचने पर दलाई लामा का स
6. 10 सितंबर को तिब्बती महिला संगठन टीडब्लूए की रजत जयंती उद्घाटन स
7. तिब्बती महिला संगठन 25 वर्ष पूरे होने पर 10 सितंबर के समारोह में तिब्बती
8. कनाडा में वैनकूवर की यात्रा के दौरान दलाई लामा और 16 हजार स्कूली बच
9. अमेरिका में शिकागो यात्रा के समय एयरपोर्ट पर दलाई लामा का स्वागत करत
10. ताइवान में आए भयंकर तूफान मोराकोट में मारे गए और प्रभावित लोगों के लि

♦ आंखों देखी

की आंख से

सिंकियांग स्वतंत्रता संग्राम की नेता राबिया कादिर के साथ दलाई लामा।

में तिब्बत की आजादी के समर्थन में एक प्रदर्शन करते तिब्बती और समर्थक।

तिब्बती कार्यकर्ता तिब्बती झंडे के साथ चीनी काफिले को रोकता हुआ।

ा मंदिर के भिक्षुओं ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की।

लामा का स्वागत करते स्थानीय नागरिक।

द्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री श्रीमती रिंछेन खांडो पुस्तक विमोचन करते हुए।

में तिब्बती संसद की उपाध्यक्षा सुश्री दोलमा ग्यारी और

स्कूली बच्चों के बीच बातचीत के लिए 29 सितंबर के दिन एक विशेष सभा का दृश्स।

ागत करते हुए स्थानीय तिब्बती नागरिक।

ोगों के लिए 25 सितंबर को विशेष प्रार्थना में भाग लिया।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

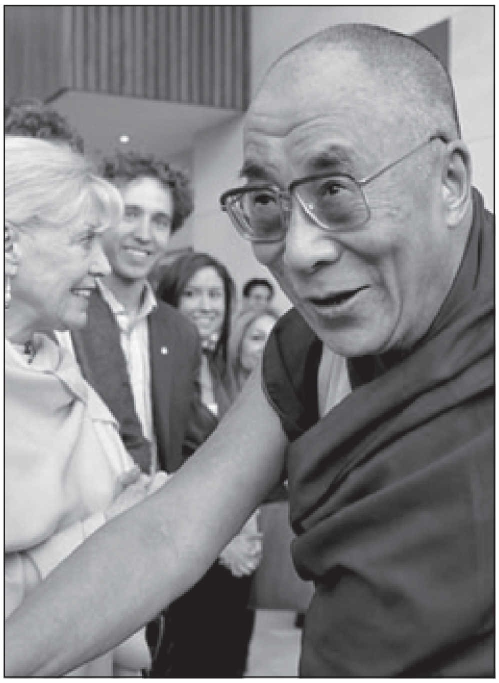

पहली पीढ़ी के निर्वासित तिब्बतियों की कहानी सार्वजनिक की गई

तिब्बतियों की आत्मकथा के रास्ते इतिहास लेखन

टीओएचपी ने कहा, ''मौखिक इतिहास का यह संग्रह अमूल्य है। टीओएचपी का वर्तमान लक्ष्य साक्षात्कारों को बिना कांट–छांट के इंटरनेट पर डालना और भावी तिब्बती पीढ़ियों, चीनी जनता, इतिहासकारों, पत्रकारों और तिब्बत समर्थकों को उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, टीओएचपी मौखिक इतिहास को चीनी मैंडारिन भाषा और कैंटोनीज में भी अनुवाद कराएगी ताकि युवा चीनी पीढ़ी समझ सके कि तिब्बत में वास्तव में क्या हुआ।

धर्मशाला, 4 अगस्त तिब्बती बुजुर्गों की निजी कहानी को दस्तावेजबद्ध करने के परम पावन दलाईलामा के निर्देश के बाद तिब्बत ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट (टीओएचपी) ने अपनी वेबसाइट http://www.tibetoralhistory.org पर पिछली पीढ़ी के 25 तिब्बतियों के अनुभव पोस्ट किए हैं।

टीओएचपी ने एक बयान जारी कर कहा कि तिब्बती बुजुर्गों के अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, चीनी फौज के आक्रमण, उसके विनाशकारी प्रभाव, चीनी बर्बरता, बेगारी, तिब्बती स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रतिरोध और निर्वासन में तिब्बतियों के पलायन के अनुभवों को भावी पीढ़ी के लिए सहेजकर रखा जाएगा।

तिब्बती जनता के सही इतिहास को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, टीओएचपी ने भारत में बायलाकुप्पे तिब्बती बस्ती और अमेरिका में रहने वाले तिब्बती बुजुर्गों के साक्षात्कार लिए। उन साक्षात्कारों के अनुवाद के साथ–साथ उनकी प्रतिलिपि तैयार की और वीडियोटेप बनाए। कुल मिलाकर 60–95 आयुवर्ग के 67 बुजुर्गों के साक्षात्कार लिए गए। ये सभी तिब्बत के तीन परंपरागत प्रांतों––खम, आम्दो और ऊत्सांग–– के मूल निवासी थे।

साक्षात्कार की प्रतिलिपि के अलावा, हर बुजुर्ग का परिचय और एक संक्षिप्त फिल्म 'यादों में तिब्बतः तिब्बती बुजुर्गों का आंखों देखा वृत्तांत' इंटरव्यू की क्लिप के साथ वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

साक्षात्कार देने वाले एक बुजुर्ग ने टीओएचपी को बताया, ''मैं तिब्बती समुदाय के बुजुर्गों में से एक हूं। यदि मैं पढ़ा–लिखा होता तो अपनी कहानी लिखता। लेकिन न तो मैं लिख सकता हूं और न ही अच्छी तरह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूं। इसलिए, मैं अपनी कहानी को कलमबद्ध नहीं कर सका। आज आपने मुझे अपनी कहानी कहने का मौका दिया है। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। मेरा मानना है कि मुझे एक सुनहरा मौका मिला है।''

इसी तरह, 82 वर्षीय एक अन्य तिब्बती शरणार्थी ने कहा, ''तिब्बत की घटनाओं के बारे में बताने के लिए मैं जीवनभर इंतजार करता रहा हूं।''

एक और तिब्बती बुजुर्ग चो ल्हामो ने कहा, ''मेरी तरह निर्वासन में रहने वाले लगभग सभी तिब्बती बुजुर्ग गुजर गए। हमारी पीढ़ी के गुजरने के बाद हमारे इतिहास का खत्म हो जाना बहुत दुखद होगा। इसीलिए तिब्बत ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है। हमारे सभी बुजुर्गों के गुजरने के बाद भी हमारी कहानी इस परियोजना के जरिए पीढ़ी–दर–पीढ़ी तिब्बतियों के पास पहुंचेगी।''

टीओएचपी ने कहा, ''मौखिक इतिहास का यह संग्रह अमूल्य है। टीओएचपी का वर्तमान लक्ष्य साक्षात्कारों को बिना कांट–छांट के इंटरनेट पर डालना और भावी तिब्बती पीढ़ियों, चीनी जनता, इतिहासकारों, पत्रकारों और तिब्बत समर्थकों को उपलब्ध कराना है।

टीओएचपी की योजना साक्षात्कारों की प्रतियां और मुद्रित प्रतिलिपियां लाइब्रेरी ऑफ तिबेतन वर्क्स ऐंड आर्काइव्स, यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और दुनियभर की अन्य लाइब्रेरियों को मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्त, टीओएचपी मौखिक इतिहास को चीनी मैंडारिन भाषा और कैंटोनीज में भी अनुवाद कराएगी ताकि युवा चीनी पीढ़ी समझ सके कि तिब्बत में वास्तव में क्या हुआ।

परम पावन दलाईलामा के विषेश दूत लोडी ग्यारी ने तिब्बत सहित दुनियाभर में रहने वाले तिब्बतियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी पीड़ा के 50 वर्षों के अनुभव को कलमबद्ध करें। ''यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमें दिवंगत तिब्बतियों को श्रद्धांजलि के रूप में अपने निजी अनुभवों को दर्ज करना चाहिए। हमें हर हाल में यह काम करना चाहिए, असंतोष भड़काने के लिए नहीं, बल्कि चीनी जनता को अपने सही इतिहास से परिचित कराने के लिए। हमें चीनी जनता को यह एहसास कराना है कि भावी तिब्बत के लिए हमारा शांतिपूर्ण संघर्ष न्यायोचित है।''

लोडी ग्यारी ने तिब्बती युवकों से खास तौर पर अपील की कि वे अपने माता–पिता और रिश्तेदारों से उनके पारिवारिक अनुभवों के बारे में सीखें। उन्होंने कहा, ''यह हमारे तिब्बती बच्चों को उत्तराधिकार में मिली विरासत का अंग है। सभी तिब्बती परिवारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने इतिहास को जानें और अपने जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं के सबूत इकट्ठा करें।''

टीओएचपी ने जिन बुजुर्गों के साक्षात्कार लिए थे, उनमें से पांच की पिछले साल मृत्यु हो गई। उनके नाम ताशी नीमा, दोरजी फुंत्सोक, खेनराब दाक्पा, वांगला और त्सेरिंग कीपा हैं। टीओएचपी ने कहा, ''यह बहुत दुखद खबर है। हमें अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।''

त्सेरिंग वांगमो, फायुल

तेरहवें दौर की बातचीत के बाद चीन–भारत सीमा संबंधी गतिरोध जारी

चीन का विस्तारवादी रूख आड़े आ रहा है

10 अगस्त भारत–तिब्बत सीमा को लेकर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 13वें दौर की बातचीत आठ अगस्त को नई दिल्ली में बगैर किसी नतीजे के समाप्त हो गई। दोनों देशों के बीच इस संबंध में बातचीत 2003 में शुरू हुई थी। दोनों देशों के बीच हाल की कुछ घटनाओं के बाद रिश्ते में आई खटास के परिणामस्वरूप तेरहवें दौर की दो–दिवसीय बातचीत एक साल के अंतराल पर आयोजित की गई थी। हालांकि यह बातचीत विश्वास बहाली के उपायों के रूप में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों – डॉ. मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ– के बीच हॉटलाइन शुरू करने के फैसले के साथ समाप्त हो गई।

उल्लेखनीय है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में चल रही एक भारतीय परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से मिल रहे ऋण को रोकने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने की भारत की पहल को असफल करने का प्रयास किया था। चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व की भांति स्टेट काउंसलर दाई बिंगुओ ने किया जबकि भारत का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन ने किया। दोनों देशों के बीच अंतिम दौर की बातचीत सितम्बर 2008 में आयोजित की गई थी।

सात अगस्त को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जियांग यु ने इस बारे में हांगकांग के एक चीन–समर्थक समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों को निराधार करार दिया। चीनी भाषा के समाचार पत्र मिंग पाओ ने पांच अगस्त को खबर दी थी कि चीन पूर्वोत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश संबंधी अपनी मांग छोड़ देगा बशर्ते भारत 33,000 किलोमीटर में फैले अक्षय चीन इलाके पर अपना हक जताना छोड़ दे और मध्य क्षेत्र में दो हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को 'लौटा' देगा। लेकिन चीन के सरकारी समाचार पत्र 'चाइना डेली' में आठ अगस्त को चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परैरी इंटरनेशनल रिलेशन्स में दक्षिण एशिया विशेषज्ञ फु शियाओचियांग के हवाले से लिखा गया कि मिंग पाओ में प्रकाशित समाचार भारत के बयान पर आधारित है।

चाइना डेली ने आठ अगस्त को लिखा कि चीन और भारत की सीमाएं करीब दो हजार किलोमीटर एक–दूसरे से जुड़ी हैं, जिसके तहत 125,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विवादित हिस्सा है। चीन ने पहले ही संकेत दे रखा है कि अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण तवांग इलाके को भारत द्वारा लौटाने की स्थिति में ही वह अन्य इलाकों से जुड़े विवाद को सुलझाने में रुचि लेगा।

भारत के समाचार पत्र डीएनए ने 6 अगस्त को प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा है कि सीमा संबंधी बातचीत तावांग के मुद्दे पर 2007 से ही अटकी हुई है और इसके सुलझने के आसार कम ही नजर आते हैं। चीन ने इस इलाके पर यह कहते हुए दावा किया है कि तिब्बती इसे छठे दलाई लामा की जन्मस्थली के रूप में हासिल करना चाहते हैं। यद्यपि मौजूदा दलाई लामा ने स्पष्ट किया है कि 1914 के मैकमोहन लाइन समझौते के समय से ही यह इलाका भारत का हिस्सा है। लेकिन चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने सात अगस्त को लिखा कि चीन सरकार ने इस समझौते को कभी मान्यता प्रदान नहीं की है।

सीमा विवाद पर राजनीतिक मानदंड और निर्देशक सिद्धांतों को लेकर एक समझौते पर अप्रैल 2005 में तब हस्ताक्षर किये गए थे, जब प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने दिल्ली की यात्रा की थी। उस समझौते में कहा गया है कि आबादी वाले इलाके सीमा विवाद के हल के लिए भूभागों के आदान–प्रदान का हिस्सा नहीं होंगे। चीन 2007 से ही इस वायदे से मुकरता आ रहा है।

तिबेतन रिव्यू से साभार

चीन ने अरुणाचल प्रदेश में चल रही एक भारतीय परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से मिल रहे ऋण को रोकने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने की भारत की पहल को असफल करने का प्रयास किया था।

निर्वासित पत्रकारों ने तिब्बत में जाने देने की मांग की

धर्मशाला, 2 अप्रैल निर्वासित तिब्बती पत्रकारों के एक समूह एसोसिएशन आफ टिबेटन जर्नलिस्ट्स (एटीजे) ने चीन जनवादी गणतंत्र की सरकार से मांग की है कि उनके सदस्यों को निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए तिब्बत के अंदर जाने की इजाजत दी जाए।

एटीजे के अध्यक्ष ताशी वांगचुक ने कहा था कि पिछले साल मार्च में जब समूचे तिब्बत में चीनी उपनिवेशवादी कब्जे के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था और चीनी सैनिकों ने उसका कठोर दमन किया था, उसके बाद चीन ने तिब्बत में बहुत कम पत्रकारों को जाने की इजाजत दी है और जो जाते भी हैं तो उनके दौरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में हुई घटनाओं के बाद से ही तिब्बत में अघोषित रूप से सैन्य शासन लागू है।

दलाई लामा लद्दाखी बच्चों के साथ – नई आशा की रोशनी

दलाई लामा ने लद्दाख के बच्चों के लिए स्कूल का उद्घाटन किया

उपेक्षित इलाकों के बच्चों के लिए नई आशा

धर्मशाला, 18 अगस्त तिब्बत के निर्वासित शासक और धर्मगुरू परमपावन दलाई लामा ने 14 अगस्त को लद्दाख क्षेत्र के सुदूर इलाकों जांस्कार, कारगिल और नुब्रा घाटी के वंचित बच्चों के लिए एक विद्यालय का उद्घाटन किया। जामयांग स्कूल का निर्माण दलाई लामा के चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किया गया है और प्रबंधन नालन्दा धर्म सेंटर, लेह के हाथों में है।

लद्दाख क्षेत्र के सुदूर इलाकों जांस्कार, कारगिल और नुब्रा घाटी के वंचित बच्चों के लिए एक विद्यालय का उद्घाटन किया। जामयांग स्कूल का निर्माण दलाई लामा के चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किया गया है और प्रबंधन नालन्दा धर्म सेंटर, लेह के हाथों में है।

परमपावन दलाई लामा ने स्कूल प्रशासन को बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं तिब्बती बौद्धधर्म की शिक्षा प्रदान करने की सलाह दी। जामयांग स्कूल की सचिव त्शेरिंग सोनम ने कहा, ''हमारे बोर्ड के प्रतिनिधि और सुदूर इलाकों के प्रतिनिधि तथा जामयांग स्कूल के निदेशक इन इलाकों का भ्रमण करते हैं और उसके बाद मौलिक शिक्षा से वंचित बच्चों का चयन करके उनके नामांकन को मंजूरी प्रदान करते हैं।''

इस स्कूल में नामांकित विद्यार्थियों का पहला जत्था लद्दाख के दा–हानू इलाके के घुमंतू कबिलाई या द्रोग्पा समुदाय के हैं। पांचवीं कक्षा तक चलने वाले इस स्कूल में छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं। करीब 60 वंचित बच्चों ने फिलहाल स्कूल में प्रवेश लिया है।

दार्जिलिंग में तिब्बत समर्थक समूह गठित

18 अगस्त निर्वासित तिब्बती पार्लियामेंट ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नवगठित तिब्बत समर्थन समूह (टीएसजी) के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी है।

समूह का गठन 22 जून को किया गया था। इस समूह में 27 कार्यकारी सदस्य हैं, जो दार्जिलिंग के अनेक गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य भी हैं। इन संगठनों में ऑल इंडिया तमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन, शेरपा बुद्धिस्ट एसोसिएशन, हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, तिबेतन मुस्लिम एसोसिएशन, योल्मो बुद्धिस्ट एसोसिएशन, धर्मचक्र कमेटी, मंजूश्री सेंटर ऑफ तिब्बत बुद्धिस्ट एसोसिएशन, सिक्किमीज डेन्झोंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन, किधू चु, चागपोरी तिबेतन मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टुडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत और मरकज गोन्पा शामिल हैं।

समूह के सदस्यों को 14 अगस्त को भेजे गए एक पत्र में डिप्टी स्पीकर श्रीमती डोल्मा ग्यारी ने कहा, ''निर्वासित तिब्बती पार्लियामेंट की स्थायी समिति इस बात को लेकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही है और इसलिए हम तिब्बत समर्थन समूह के सफल गठन के लिए हार्दिक बधाई देते हैं।''

श्रीमती ग्यारी ने कहा, ''हम दार्जिलिंग में गठित इस समर्थन समूह के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को हार्दिक बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि यह समूह तिब्बती समस्या के समाधान के लिए जारी प्रयास में एक नया अध्याय जोड़ेगा।''

टीपा की स्वर्ण जयंती

तिबेतन रिव्यू, 14 अगस्त तिबेतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफार्मिंग आर्ट्स (टीपा) ने 11 अगस्त को एक भव्य संगीत समारोह के साथ अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। संगीत समारोह में सालाना ट्रॉफी के लिए इंस्टीट्यूट के दो सदनों––ग्यालू और गोंपा––के बीच मुकाबला था। भारतीय अधिकारियों और तिब्बत की निर्वासन सरकार के अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की संपर्क अधिकारी सुश्री मणिका जैन ने पुरस्कार वितरण किया। उन्होंने कहा कि भारत तिब्बती सांस्कृतिक विरासत और तिब्बती बच्चों की ीिक्षा के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए समर्थन देता रहेगा।

तिब्बती निर्वासन सरकार की संस्था टीपा अभी तक 110 शिक्षकों सहित 483 पेशेवर कलाकारों को प्रशिक्षण दे चुकी है। ये कलाकार भारत और विदेश में सैंकड़ों प्रभावशाली प्रस्तुतियां कर चुके हैं।

टीपा के निदेशक श्री वांगचुक फासुर ने निर्वासन में तिब्बती धर्म और संस्कृति को संरक्षण तथा प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और भारतीय जनता का आभार व्यक्त किया

दलाई लामा ने समाज में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया

धर्मशाला, 3 अगस्त परम पावन दलाईलामा ने जर्मन दैनिक बिल्ड के रविवारीय संस्करण को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वरिष्ठ पदों पर अधिक–से–अधिक महिलाओं को रखा जाना चाहिए।

दलाईलामा ने कहा, ''महिलाओं में अधिक करुणा होती है और वे पुरुषों की तुलना में दूसरों की पीड़ा को जल्दी समझ सकती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं को शामिल करना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना चाहिए। जर्मनी में एक महिला का चांसलर बनना इसकी मिसाल है।''

परम पावन दलाईलामा बाहरी रूप–रंग के प्रति आसक्ति को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा, ''जो अपने रूप–रंग से खुश है, उसे बाहरी आकर्षण के लिए आपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति की अंदरूनी सुंदरता उसके चेहरे पर झलकती है और वह दूसरों को स्वतः सुंदर लगता है।''

तिब्बती महिलाओं ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को धन्यवाद ज्ञापित किया

धर्मशाला, 14 अगस्त (फायुल) तिबेतन वीमेन्स एसोसिएशन (टीडब्ल्यूए) ने तिब्बती समस्या के सिलसिले में अथक समर्थन देने के लिए भारत को उसके 62वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गांगचेन कीशोंग में विशेष भोज का आयोजन किया। इस लंच में कांगड़ा जिले के 26 से अधिक भारतीय अधिकारी और 100 से अधिक भारतीय मित्र आमंत्रित थे।

कालोन ट्रीपा अर्थात् प्रधानमंत्री सामदोंग रिंपोछे ने इस समारोह की अध्यक्षता की और तिब्बतियों को धर्मशाला में पिछले पचास वर्षों से अधिक से आश्रय उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडो–तिब्बतन फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष अजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि वह निर्वासित तिब्बतियों और परमपावन दलाई लामा की धर्मशाला में पावन उपस्थिति के लिए आभारी हैं।

टीडब्ल्यूए की अध्यक्ष कीर्ति डोल्कर ल्हामो और संयुक्त सचिव तेन्जिन डोल्मा ने उपस्थित जनसमुदाय को हिन्दी में संबोधित किया। टीडब्ल्यूए की क्षेत्रीय शाखा ने भी भारतीयों के सहयोग और एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

टीडब्ल्यूए ने एक बयान में कहा है कि वह भारत

महिला संघ के समारोह में सुश्री रिंछेन खांडो और ग्यारी दोलमा – देश को समर्पित

सरकार और भारतीय जनता के ऋणी हैं। उन्होंने कहा, ''तिब्बतियों को फलने–फूलने का मौका देने और अभाव के समय में हर संभव सहयोग करने के लिए हम भारत को धन्यवाद देते हैं। हम भारत को सर्वाधिक मानवतावादी देश होने पर धन्यवादी हैं। हमें भरोसा है कि यह उदार देश हमेशा सफलता की ओर कदम बढाएगा और प्रतिष्ठा हासिल करेगा।

धर्मशाला में तिब्बती शहीदों की याद में स्मारक बनेगा

धर्मशाला 7 अगस्त तिब्बत की निर्वासन संसद ने तिब्बत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले सभी तिब्बतियों की याद में धर्मशाला में एक प्रस्तर स्तंभ खड़ा करने का फैसला किया है। यह जानकारी इस योजना की देखरेख के लिए बनी एक संसदीय समिति ने दी।

सभी बहादुर तिब्बतियों के योगदान के सम्मान में स्मारक बनाने का फैसला इस साल मार्च में 14वीं तिब्बती संसद के सातवें अधिवेशन में लिया गया था।

समिति ने कहा कि उसने स्तंभ के बेहतरीन डिजाइन के लिए तिब्बती लोगों से राय मांगी है। समिति प्राफेशनल कलाकारों और डिजाइनरों के रचनात्मक काम की एक सूची से स्तंभ के लिए बेहतरीन आर्ट और डिजाइन चुनेगी। सर्वोत्तम कलात्मक काम के लिए 5,000 रु. दिए जाएंगे जबकि डिजाइनर का नाम स्तंभ पर अंकित किया जाएगा। डिजाइनर को संसद सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित करेगी।

समिति ने स्तंभ की लंबाई–चौड़ाई चार–चार फुट और ऊंचाई 12 फुट तय किया है।

दलाईलामा ने कहा, ''महिलाओं में अधिक करुणा होती है और वे पुरुषों की तुलना में दूसरों की पीड़ा को जल्दी समझ सकती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं को शामिल करना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना चाहिए।

सिंकियांग में आंदोलनकारियों के मुकदमे की सुनवाई की तारीख से इन्कार

मुकदमे केवल उइगुरों पर चलेंगे

बीजिंग, 25 अगस्त चीन के पश्चिमोत्तर सिंकियांग इलाके की सरकार ने सरकारी मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है कि इलाके में जुलाई की जातीय अशांति से संबंधित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

सिंकियांग के सरकारी मीडिया कार्यालय के एक अधिकारी ली हुआ ने एएफपी को बताया, ''फिलहाल मुकदमे की सुनवाई की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। मुझे नहीं मालूम कि चाइन डेली को किस सूत्र से यह खबर मिली है। लेकिन यह सत्य नहीं है। हम इसकी सुनवाई की तारीख समय आने पर मीडिया को अवश्य करेंगे।''

उरुम्ची, काशगर और काशी में गत जुलाई के प्रारम्भ में कम से कम 197 लोग उस वक्त मारे गए थे जब स्थानीय मुस्लिम उइगुर अल्पसंख्यकों और हान चीनी समुदाय के लोगों के बीच भिडंत हो गई थी। यह हाल के दशकों में भड़की सबसे गंभीर जातीय हिंसा थी। उइगुर के सूत्रों ने दावा किया है कि चीनी हान समुदाय के प्रवासियों और सुरक्षा बलों द्वारा 800 से अधिक उइगुर अल्पसंख्यक मारे गए हैं।

5 से 8 जुलाई के बीच ये दंगे चीन के कैंटन शहर में 25 जून को चीनी युवाओं द्वारा 18 उइगुर युवा मजदूरों की हत्या के जवाब में हुए थे। पहले दिन उइगुरों के हिंसक हमले के जवाब में अगले तीन दिन चीनी सुरक्षा बलों और वहां लाकर बसाए गए चीनियों के हमलों में 800 से अधिक उइगुरों को मार डाला गया था।

5 से 8 जुलाई के बीच ये दंगे चीन के कैंटन शहर में 25 जून को चीनी युवाओं द्वारा 18 उइगुर युवा मजदूरों की हत्या के जवाब में हुए थे। पहले दिन उइगुरों के हिंसक हमले के जवाब में अगले तीन दिन चीनी सुरक्षा बलों और वहां लाकर बसाए गए चीनियों के हमलों में 800 से अधिक उइगुरों को मार डाला गया था। मुकदमे केवल उइगुरों पर चलेंगे।

ली ने चाइना डेली की उस खबर का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि आरोपितों की संख्या 200 से अधिक है। इससे पहले सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया था कि केवल 83 लोगों को औपचारिक तौर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, ''हमें संदिग्धों की संख्या के बारे में सरकारी नोटिस नहीं मिला है। इसलिए संदिग्धों की संख्या अभी तक 83 ही है।''

चाइना डेली ने अपनी रिपोर्ट में अदालत परिसर के चारों ओर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये जाने और स्थानीय लोगों के हवाले से कहा है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा जिन्होंने इस आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया।

गिरफ्तारी के बाद तिब्बती लेखक ताषी का कोई अता–पता नहीं

धर्मशाला, 3 अगस्त, द तिब्बत पोस्ट इंटरनेशनल तिब्बत की एक समाचार वेबसाइट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने हाल में तिब्बती लेखक ताशी राब्तेन (थेरांग) का अपहरण कर लिया। ताशी पर विध्वंसक राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ताशी ने 25 जनवरी को ''ब्लड लेटर'' षीर्शक से एक किताब प्रकााित की थी।

उनके समर्थकों का कहना है कि इस किताब में पिछले साल 10 मार्च को तिब्बत में हुए विरोध प्रदर्शनों का ईमानदारीपूर्ण और सटीक वर्णन है। लेकिन चीनी सरकार ने ''ब्लड लेटर'' का वितरण रोक दिया और बिकी हुई प्रतियों को जब्त कर लिया। यही नहीं, उसने पुस्तक की 'संदिग्ध' राजनैतिक विषयवस्तु के कारण उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया। चीनी अधिकारियों ने लेखक की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखनी और उनसे गुप्त पूछताछ भी शुरू कर दी थी। और अब ताशी का कहीं अता–पता नहीं है। ताशी के 'ब्लड लेटर' में एक भूमिका (जिसमें 32 लेख हैं) और पांच मुख्य खंड हैं। इन खंडों के शीर्शक 'नर्क से एक संदेश', 'रूह का गीत', 'मेरा तिब्बत', 'दिल का बलिदान' और 'सच का प्रतिशोध' हैं। इन अध्यायों में, और चीनी नॉर्थवेस्ट माइनॉरिटीज युनिवसटी की सालाना पत्रिका जियार दोंग री (द कॉन्चशेल ऑव दि ईस्ट) में प्रकाशित कई लेखों में ताशी ने 10 मार्च 2008 को हुए रक्तपात का ब्यौरा दिया है। यह रक्तपात उस समय हुआ जब चीनी पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हिंसक तरीका अख्तियार कर लिया। ताशी का तर्क है कि हिंसा और जान–माल के नुकसान के लिए तिब्बती नहीं, बल्कि चीनी अधिकारी दोशी थे।

इस दावे की पुष्टि उस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट से भी होती है जो सिंगापुर के एक पत्रकार ने भेजी थी। यह रिपोर्ट विरोध प्रदर्शनों के दौरान छपी थी। इसके अतिरिक्त, विरोध प्रदर्शनों के दौरान ल्हासा में पढ़ने वाली एक बर्मी महिला का कहना है कि उसने एक हथियारबंद चीनी अधिकारी को तिब्बती कपड़े उतारकर पुलिस यूनिफॉर्म पहनते देखा था। फिर, हिंसा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले तथाकथित प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन के बाद गायब हो गए। यही नहीं, चीनी सरकारी मीडिया ने हिंसा की खबर सेंसर करने के बाद प्रसारित की।

ताशी ने दमनकारी चीनी शासन के मातहत

तिब्बतियों की पीड़ा का जो ब्यौरा दिया है और तिब्बती कौम तथा संस्कृति के प्रति जो निष्ठा व्यक्त की है, उसके कारण चीनी सरकार उन पर कड़ी नजर रखने लगी। और अब उनका कहीं अता–पता नहीं है।

तिब्बती भाषा में चीन के सरकारी पत्र 'पीपल्स डेली' का प्रकाशन शुरू

तिबेतन रिव्यू, 3 अगस्त चीन के उपनिवेशवादी कब्जे के प्रति तिब्बती जनता की सहमति पाने के लिए अब चीन सरकार तिब्बती भाषा में चीन का प्रमुख अखबार 'पीपल्स डेली' प्रकाशित करने जा रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार उसके मुखपत्र पीपुल्स डेली का प्रकाशन अब तिब्बती भाषा में भी शुरू किया गया है। इसके जरिए चीन यह दिखाना चाहता है कि वह तिब्बती संस्कृति की उपेक्षा नहीं कर रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, पीपुल्स डेली और तिब्बत डेली ने तिब्बती भाषा में चार पृष्ठों का पहला संस्करण 1 अगस्त को निकाला। तिब्बती भाषा में निकलने वाले पार्टी के इस मुखपत्र को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और पड़ोस के सिचुआन, युन्नान, चिंघाई और गांसू प्रांतों के तिब्बती बहुल इलाकों में वितरित किया जाएगा।

बीजिंग स्थित पीपल्स डेली के संपादकीय कार्यालय के एक बयान के मुताबिक, तिब्बती भाषा का संस्करण तिब्बत की राजधानी ल्हासा, सिचुआन की राजधानी चेंगदू और चिंघाई की राजधानी सिनिंग में छपेगा।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तिब्बती भाषा का संस्करण अपने समाचार कवरेज के जरिए तिब्बत में आथक विकास, सामाजिक प्रगति, जातीय सौहार्द्र और स्थिरता में योगदान करेगा।

सिन्हुआ ने पीपुल्स डेली के हवाले से यह भी कहा कि अखबार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख दिशानिर्देशों और केंद्र सरकार की नीतियों तथा उसके फैसलों को प्रकाशित करेगा।

चीन में बंधुआ मजदूरी, दासप्रथा, मानव तस्करी बदस्तूर जारी

तिब्बत पर अपना उपनिवेशवादी शासन जारी रखने को जायज ठहराने के लिए चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी लगातार यह दावा करती आयी है कि चीनी शासन लागू होने से पहले तिब्बत में दासप्रथा और सामंती शोषण बड़े पैमाने पर व्याप्त था। लेकिन इसका सबसे दुःखद पहलू यह है कि आधुनिक चीन में शर्मसार कर देने वाली दासप्रथा आज भी जारी है। इसके शिकार लोगों में मानसिक रूप से विकलांग लोग और बच्चे भी शामिल हैं। चीन और उसके आधिपत्य वाले तिब्बत में बच्चों के लापता होने के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन कानून–व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इन बच्चों को दास बनाने वाले मालिकों के खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई हो पाती है। कम ही ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बच्चों को दास बनाकर रखने वाले लोग पकड़े गए हों या उन्हें सजा मिली हो।

ऐसे ही एक ताजा मामले में पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत की पुलिस ने ईंट–भट्ठों में काम करने वाले लोगों की पिटाई करने और मानसिक रूप से विकलांग 32 लोगों पर काम के लिए जोर–जबरदस्ती करने के मामले में 10 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने गत 22 मई को खबर दी थी कि 80 पुलिसकर्मियों के एक दल ने गत 28 अप्रैल को जेशोऊ शहर स्थित ईंट–भट्ठों पर छापे मारे और वहां से बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। समिति ने स्थानीय पुलिस प्रमुख गेओ जी के हवाले से खबर दी है, ''उनमें से सभी 25 से 45 वर्ष तक के आयुवर्ग के हैं और मानसिक रूप से विकलांग हैं।'' उनलोगों को बगैर वेतन के प्रतिदिन 10 घंटों से भी अधिक कठिन परिश्रम करने को मजबूर किया जाता था। उनमें से कुछ के शरीर पर बेरहमी से की गई पिटाई के निशान भी थे।

ईंट–भट्ठा मालिक झांग ने पुलिस को बताया था कि उसने पड़ोसी प्रांत शांगदोंग से इन मजदूरों को खरीदा था और इसके लिए उसने मानव तस्करी में लिप्त एक टैक्सी चालक को अलग–अलग मौकों पर प्रति व्यक्ति 200 से 300 युआन का भुगतान किया था। बेचे गए ये लोग अनहुई, शांगदोंग, हेनान, हुनान, हुबेई और अन्य प्रांतों के थे। एक मामला 2007 में उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब उत्तरी शांक्सी प्रांत में एक ईंट–भट्ठा मालिक के यहां 360 विकलांगों सहित 1340 लोगों को बंधक पाया गया था।

सात विभिन्न मामलों में 29 ईंट–भट्ठा मालिकों, फोरमैन, सुपरवाइजरों एवं अन्य कामगारों के खिलाफ अदालती कार्यवाही की जा रही है। सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के हवाले से खबर दी गई है कि पुलिस ने नौ अप्रैल से चार मई तक मानव तस्करी में लिप्त 72 गुटों का पर्दाफाश कर 194 बच्चों और 214 महिलाओं को मुक्त कराया। ज्यादातर घटनाएं गुझोऊ, जियांगसु, गुआंगडोंग, शांगदोंग, हेनान और शांक्सी प्रांतों में हुईं जो चीन के अग्रणी औद्योगिक इलाके हैं।

ईंट–भट्ठा मालिक झांग ने पड़ोसी प्रांत शांगदोंग से इन मजदूरों को खरीदा था और इसके लिए उसने मानव तस्करी में लिप्त एक टैक्सी चालक को अलग–अलग मौकों पर प्रति व्यक्ति 200 से 300 युआन का भुगतान किया था। बेचे गए ये लोग अनहुई, शांगदोंग, हेनान, हुनान, हुबेई और अन्य प्रांतों के थे। एक मामला 2007 में उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब उत्तरी शांक्सी प्रांत में एक ईंट–भट्ठा मालिक के यहां 360 विकलांगों सहित 1340 लोगों को बंधक पाया गया था।

चीनी दबाव में संयुक्त राष्ट्र की समिति

तिब्बती मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट को शामिल किए जाने से निराशा

टीसीएचआरडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बतियों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके पर्यावरण और संसाधन का दोहन किया जा रहा है, उन्हें जबर्दस्ती विस्थापित किया जा रहा है, शिक्षा में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और तिब्बती बंजारों की जीवनशैली खत्म की जा रही है।

धर्मशाला, 7 अगस्त (फायुल) तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने संयुक्त राष्ट्र संघ नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (सीईआरडी) के 75वें अधिवेशन में अपनी 'वैकल्पिक रिपोर्ट' न पेश किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। धर्मशाला स्थित इस तिब्बती एनजीओ ने इसके लिए सीईआरडी सचिवालय को जिम्मेदार ठहराया। सचिवालय में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के कर्मचारी गैरसरकारी संगठनों की वैकल्पिक रिपोर्टों की जांच–पड़ताल करते हैं।

सीईआरडी ने आज चीनी गणराज्य की 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं सरकारी रिपोर्ट की जांच की। टीसीएचआरडी ने अपनी रिपोर्ट जून 2009 में भेजी थी लेकिन सीईआरडी ने उसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट नहीं किया। सीईआरडी ने टीसीएचआरडी से कहा था कि वह अपनी रिपोर्ट से 'तिब्बत पर चीनी कब्जा' वाक्यांश को हटा दे। रिपोर्ट में इस वाक्यांश का इस्तेमाल छह बार हुआ था। सीईआरडी ने रिपोर्ट के अंतिम अनुच्छेद से 'सांस्कृतिक संहार' शब्दों को भी हटाने के लिए कहा था।

टीसीएचआरडी ने अपने बयान में कहा, ''सचिवालय का निर्देश टीसीएचआरडी) को मान्य नहीं है क्योंकि यह न केवल तथ्यात्मक त्रुटि होगी, बल्कि चीनी गणराज्य के परोक्ष आदेशों को भी स्वीकार करना होगा। इस तथ्य को दुनियाभर में स्वीकार किया जाता है कि तिब्बत पर विदेशी कब्जा है। दुनियाभर में यह भी मान्य सचाई है कि औपनिवेशिक देश में निरंतर भेदभाव किया जाता है।''

टीसीएचआरडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बतियों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके पर्यावरण और संसाधन का दोहन किया जा रहा है, उन्हें जबर्दस्ती विस्थापित किया जा रहा है, शिक्षा में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और तिब्बती बंजारों की जीवनशैली खत्म की जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि सीईआरडी सचिवालय ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर चीनी सरकार के छद्म एनजीओ रिसर्च सेंटर फॉर एथनिक ईशूज इन चाइना की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। टीसीएचआरडी ने सीईआरडी सचिवालय के निर्देश को ''टीसीएचआरडी सहित सिविल सोसाइटी संगठनों के अधिकारों का हनन'' करार दिया है।

यह आशा व्यक्त करते हुए कि सीईआरडी के विषेशज्ञ चीनी सरकार की रिपोर्ट की पूरी गहराई से जांच करेंगे, तिब्बती एनजीओ ने कहा कि तिब्बत पर विदेशी कब्जा है, इसलिए वह सीईआरडी सचिवालय के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है।

टीसीएचआरडी को जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में 20–24 अप्रैल 2009 तक चले संयुक्त राष्ट्र नस्लवाद समीक्षा कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से रोक दिया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि 2001 में डर्बन में नस्लवाद के खिलाफ विश्व सम्मेलन में टीसीएचआरडी को मान्यता दी गई थी। उस समय जनरल असेंबली ने विश्व कॉन्फ्रेंस में टीसीएचआरडी की मान्यता के पक्ष में वोट दिया था।

मारबुर्ग यूनिवर्सिटी ने दलाईलामा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी

मारबुर्ग, जर्मनी, 3 अगस्त जर्मनी की युनिवर्सिटी ऑफ मारबुर्ग ने आज परम पावन दलाईलामा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मारबुर्ग में भारतीय एवं तिब्बती अध्ययन विभाग की स्थापना 1845 में हुई थी। यह विभाग बहुत छोटा होने के बावजूद काफी उर्वर है। यूनिवर्सिटी की विदेशी भाषा फैकल्टी के प्रो. युर्गन हनेदेर ने कहा कि यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि परम पावन दलाईलामा ने सत्तर के दशक में तिब्बती भाषा के प्राध्यापकों को मारबुर्ग भेजने के लिए यूनिवर्सिटी से खुद संपर्क किया था।

प्रो. डॉ. एकहर्ड बांगेर्त (भिक्खु पसादिक) ने कहा, ''परम पावन दलाईलामा की वैज्ञानिक उपलब्धियों और उनके उत्कर्ष के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है। उन्होंने ज्ञान, शिक्षा और भारतीय–तिब्बती दर्शन के विस्तार के लिए अथक प्रयास किया। परम पावन दलाईलामा ने 50 साल पहले तिब्बत छोड़ने और भारत पहुंचने के तुरंत बाद तिब्बती जनता के लिए संविधान तैयार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। वे आधुनिक दुनिया की बदलती परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं और बुद्ध के लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं।''

समारोह के बाद परम पावन दलाईलामा मारबुर्ग से लूसेन (स्विट्जरलैंड) रवाना हो गए जहां उन्होंने ''पथ के तीन मुख्य पहलुओं'' पर व्याख्यान दिया। लगभग 200 लोगों ने दलाईलामा का स्वागत किया।